भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2324

उत्तर देने की तारीखः 08.07.2019

नए आईआईटी को आरंभ करना

2324. श्री एस. मुनिस्वामीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) आरंभ करने के लिए राज्य-वार स्थानों की पहचान की है;

(ख) इन क्षेत्रों के चयन के लिए मानदंड क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): बजट घोषणा 2014-15 और 2015-16 के अनुसरण में, तिरुपति (आंध्र प्रदेश), पलक्कड़ (केरल), जम्मू (जम्मू और कश्मीर), गोवा (गोवा), भिलाई (छत्तीसगढ़) और धारवाड़ (कर्नाटक) प्रत्येक में एक-एक अर्थात् 6 नए आईआईटी स्थापित किए गए हैं। अस्थायी परिसर, जहां से वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कार्य कर रहे हैं, का ब्यौरा और स्थायी परिसरों के लिए अभिचिह्नित स्थलों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	आईआईटी का नाम	अस्थायी परिसर	स्थायी परिसर
1.	आईआईटी तिरुपति	चाडलवाडा वैंकट सुब्बैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रेनीगुन्ता रोड, तिरुपति	मेरलापाका गांव, येरपेडू (मंडल), चित्तूर जिला
2.	आईआईटी पलक्कड़	अहिल्या एकीकृत परिसर, पलक्कड़	पुडुस्सेरी वेस्ट, पलक्कड़
3.	आईआईटी जम्मू	केसीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जम्मू	खानपुर नगरोटा

4.	आईआईटी भिलाई	गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर	कुटेलभाटा और सिरसा गांव, भिलाई, दुर्ग
5.	आईआईटी धारवाड़	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (डब्ल्यूएएलएमआई)	केलागरी गांव, धारवाड़
6.	आईआईटी गोवा	गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिसर, फार्मागुडी, पोंडा	संगुएम और क्वेपम तालुका, साउथ गोवा

जहां तक स्थलों के चयन संबंधी मानदंडों का संबंध है, संबंधित राज्य सरकार से आवश्यक सामाजिक और भौतिक अवसंरचना जैसे कि सड़क, रेल तथा एयर कनेक्टीविटी, निःशुल्क और सभी कानूनी बाधाओं से मुक्त 500-600 एकड़ के कम-से-कम दो स्थलों की पहचान करने को कहा गया है। निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से युक्त स्थल चयन समिति द्वारा स्थलों का निरीक्षण किया जाता है। समिति की सिफारिशों के आधार पर सबसे उपयुक्त स्थल अनुमोदित किया जाता है। सरकार ने चरण-क के अंतर्गत इन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थायी परिसरों के निर्माण हेतु 7002.42 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं, जिनमें से 1046.59 करोड़ रुपए की राशि आईआईटी की मांग के अनुसार जारी की गई है।

*****